REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

वैश्विक सूचना संतुलन हेतु 'ब्रिक्स सूचना एवं संचार व्यवस्था' की आवश्यकता

डॉ. सुमीत द्विवेदी
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ.प्र.।

प्रास्ताविक :–

मानव समाज में सम्प्रेषण की प्रक्रिया इसके आरम्भिक काल से विद्यमान रही है। मानवीय समूहों में सामाजिक अन्तक्रिया की प्रक्रिया वाणी अथवा भाषा अथवा संकेतों अथवा लिपि के माध्यम से सम्पन्न होती रही है। सम्प्रेषण के उच्च रूप, जिसे भाषा अथवा लिपि कहते हैं, के माध्यम से ही मानव एक–दूसरे से अपने अनुभवों, विचारों, विश्वासों और भावनाओं के आदान–प्रदान द्वारा समान क्रियाकलापों तथा भावनाओं को जन्म देने में सफल हुआ है। अतः मानव समूहों में सम्प्रेषण ही एकता तथा संस्कृति की निरन्तरता के संचरण का मुख्य तत्व है। संस्कृति के रूप में मानव के पास जो सामाजिक विरासत है, उस सबका आधार मानवीय सम्प्रेषण का प्रमुख रूप 'भाषा' है। मानव ने भाषा का निर्माण करके अन्तःक्रिया की समस्या को हल कर लिया है। मानव समाज ने अपनी विकास यात्रा के दौरान प्रगति के रास्ते तलाशे। इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 16वीं शताब्दी के बाद आरम्भ हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तर्क, विवेकीकरण, ज्ञानोदय का विकास हुआ। इसने मानव समाज के सभी क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी क्रम में सूचना एवं जनसंचार की नई तकनीकों का प्रादुर्भाव हुआ। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इस क्षेत्र में आविष्कारों का तांता लगा रहा। नई–नई तकनीकें विकसित होती गईं। समाचार पत्र–पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, सिनेमा, वायरलेस आदि अनेकानेक माध्यम विकसित हुये जिनसे जनसंचार का कार्य व्यवस्थित हुआ। 1960 के दशक से सेटेलाइट क्रान्ति ने जनसंचार माध्यमों की नई–नई तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। टेलीविजन, कम्प्यूटर, इण्टरनेट, माइक्रोचिप, मोबाइल फोन, टेलीटेम्स, माइक्रो तरंग आदि अनेकानेक तकनीकी आविष्कारों की झड़ी लग गई। इसे आई0टी0 युग या इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी एरा के रूप में जाना गया।

20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आयी संचार क्रान्ति ने सम्पूर्ण वैश्विक परिदृश्य को ही परिवर्तित कर दिया है। आज सैटेलाइट, कम्प्यूटर, इंटरनेट, आप्टिकल फाइबर आदि पर आधारित जनसंचार के अत्याधुनिक साधन वैश्वीकरण के प्रमुख संवाहक हैं। ये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सूचनाओं का तीव्रतम संचार कर रहे हैं। इस क्रम में राष्ट्र राज्य की सीमाएं गौण हो गई हैं। विश्वग्राम की अवधारणा साकार हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व स्तर पर एकीकरण हुआ है। इसके अधिकाधिक प्रयोग से विशेष रूप से इण्टरनेट के तीव्र विस्तार के फलस्वरूप विभिन्न क्षत्रों में मानव गतिविधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इसका प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति एवं प्रशासन पर व्यापक रूप से पड़ा है। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में इस नई प्रौद्योगिकी ने एक उल्लेखनीय विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इस क्रम में ई–गवर्नेन्स, ई–कामर्स, ई–बैंकिंग आदि के माध्यम से वैश्विक व्यापार एवं वाणिज्य का मार्ग अधिक आसान एवं व्यापक हुआ है। ई–शिक्षा ने अविश्वसनीय ढंग से शिक्षण के नए–नए आयामों का विकास किया है। ई–जर्नलिज्म ने समय और स्थान की दूरी मिटा दी है।

किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वैश्विक सूचना का यह प्रवाह संतुलित है ? भारतीय ग्रामीण अंचलों में प्रचलित एक पुरानी कहावत है कि ''अगर जमींदार के घर का कुत्ता भी मर जाए तो यह इलाके में एक बड़ी खबर होती है, लेकिन अगर किसी गरीब के घर शादी भी हो तो यह कोई खबर नहीं होती।''

वैश्विक सूचना संचार के क्षेत्र में देखें तो कमोबेश यही स्थिति हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलती है। वर्तमान समय तक सूचना का यह वैश्विक प्रवाह एकतरफा ही बना हुआ है। यानिकि विकसित से विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों की तरफ एकतरफा संचार। इस प्रकार का संचार संचार–सिद्धान्त की उस **'बुलेट थ्योरी'** पर आधारित है, जिसके अनुसार संचार बंदूक की उस गोली के समान है जो बंदूक से अपने लक्ष्य को बेधने के लिए निकलती है। इस प्रकार के सिद्धान्त में प्रतिपुष्टि या फीडबैक की कोई जगह नहीं है।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि समाचार, सूचना एवं मनोरंजन (Infotainment) के वि व्यापार में अमेरिका सहित कुछ देशों का ही वर्चस्व है। अन्य देश इन देशों पर न केवल मीडिया उत्पादों के लिए निर्भर हैं, बल्कि आर्थिक सन्दर्भ में भी निर्भर हैं। निर्भरता सिद्धान्त के प्रतिपादकों के अनुसार – निर्भरता सम्बन्धों के लिए यह आवश्यक है कि सूचनाओं, विचारों एवं संस्कृति के क्षेत्र में देश परिपक्व एवं समृद्ध हों तभी इस प्रकार के स्थायी सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं।

मोवलाना (Mowlana) ने अन्तर्राष्ट्रीय संचार के विभिन्न स्वरूपों का गहन विश्लेषण करके एक निर्भरता मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में दो आयाम महत्वपूर्ण हैं जो निर्भरता या स्वायत्तता को स्पष्ट करते हैं। ये अयाम तकनीकी एवं संचार अक्ष हैं। इस मॉडल के अनुसार प्रेषक (sender) से प्राप्तकर्ता (reciever) तक एक पारिवारिक वातावरण बन जाता है, जहां उत्पादन और वितरण व्यवस्था तकनीकी मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संचार, राष्ट्रीय जनमाध्यमों की जटिल व्यवस्था के विपरीत चार अवस्थाओं से होकर प्रवाहित होता है। ये चार अवस्थाएं उद्भव (origination), उत्पादन (production), वितरण (distribution) एवं प्राप्तिकरण (reception) हैं। ये सभी अवस्थाएं देशों की संगठनात्मक एंव सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार भिन्न–भिन्न होती हैं। किसी देश से मीडिया उत्पाद का आयात करके एकदम भिन्न मीडिया व्यवस्था द्वारा उसे उन दर्शकों/श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है जो मौलिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। सिनेमा एवं टेलीविजन के मामले में यह बात पूर्णतया लागू होती है। ये किसी देश में वहां की भाषा एवं परिवेश में निर्मित होते हैं और वितरित होते हैं अन्य देशों में। तकनीकी अक्ष से देखने से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक अवस्था, दो प्रकार के विशेषज्ञों अथवा पूंजी पर निर्भर करती है। एक का सम्बन्ध यन्त्रों से होता है जिनमें कैमरा, स्टूडियो, मुद्रण यन्त्र, कम्प्यूटर, ट्रान्समीटर, संचार उपग्रह आदि आते हैं और दूसरे का सम्बन्ध कार्यप्रणाली से होता है जिनमें विषयवस्तु, प्रबन्धन, प्रस्तुतीकरण, प्रसारण, विज्ञापन तथा शोध आदि शामिल होते हैं। उत्पादन एवं वितरण दोनों ही अवस्था में संचार प्रक्रिया आन्तरिक एवं बाह्य मीडिया व्यवस्था से प्रभावित होती है। उत्पादन प्रक्रिया उत्पादक देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना से प्रभावित होती है जबकि वितरण अथवा विपणन प्रक्रिया को देश की अर्थव्यवस्था एवं मीडिया विशेष का बाजार प्रभावित करता है।

ब्रिक्स देशों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रूस को छोड़कर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एवं चीन दशकों से ऐसे देशों में शामिल रहे हैं, जिनकी संचार व्यवस्था का संचालन इसी आधार पर होता है। इन देशों में प्रयोग किये जाने वाले संचार संसाधन पश्चिम/विकसित देशों से आयात किये जाते रहे हैं, साथ ही साथ इन देशों में प्रकाशित एवं प्रसारित किये जाने वाले समाचारों एवं कार्यक्रमों पर भी आयातित संस्कृति एवं सभ्यता की भरपूर झलक देखने को मिलती है। ऐसे कार्यक्रमों ने न केवल इन देशों के समाज एवं संस्कृति में अनधिकृत हस्तक्षेप किया है, वरन इन देशों की राजनीतिक एवं आर्थिक दिशा में भी अपने अनुसार परिवर्तन किया है। आज भी दुनिया की सभी बड़ी संचार एजेन्सियां एपी, एफपी, रायटर, एपीटीएन आदि विकसित देशों द्वारा संचालित की जा रही हैं, जो विश्व संचार के लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इसके अलावा इन देशों में संचार के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले लगभग सभी प्रमुख उपकरण भी विकसित एवं पश्चिमी देशों से ही आयातित किये जाते हैं। यही नहीं वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक माध्यम का दर्जा प्राप्त कर चुके न्यू मीडिया/सोशल मीडिया की प्रमुख वेबसाइटों का संचालन भी विकसित देशों द्वारा ही अपनी शर्तों के मुताबिक किया जा रहा है, फिर

चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो या फिर सर्च इंजन गुगल एवं शहू। इन वेबसाइटों के संचालन के लिए बनाए जाने वाले ज्यादातर नियम–कानून पश्चिमी देशों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया द्वारा प्रसारित सूचनाओं एवं मीडिया के राजनीतिक इस्तेमाल की घटनाएं पुरानी बात हो गई है। मीडिया के राजनीतिक प्रयोग की घटनाएं द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त शीतयुद्ध के काल में सर्वाधिक हुई। शीत युद्ध के दौरान विश्व की घटनाओं को पाश्चात्य देशों की मीडिया द्वारा तोड़–मरोड़कर प्रसारित किया जाने लगा। इसका प्रमुख कारण पाश्चात्य देशों और विशेषकर अमेरिका की विदेश नीति रही है। लगभग सभी पाश्चात्य देशों की मीडिया ने अमेरिका की विदेश नीति के प्रभाव में रहकर काम किया। इसके परिणामस्वरूप गुट निरपेक्ष देशों और पाश्चात्य देशों विशेषकर अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद की खाई विस्तृत होने लगी। ईरान, निकारागुआ, क्यूबा, वियतनाम और कुवैत में अमेरिकी हस्तक्षेप को पश्चिमी मीडिया द्वारा जिस प्रकार से जायज ठहराया गया, वह भारत, दक्षिण अफ्रीका सहित निरपेक्ष देशों के लिए चिन्ता का एक बड़ा कारण बना। इस विवाद के हल के लिए तथा सूचना के स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रवाह के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार विचार विमर्श किए गए। इस विचार विमर्श में गुट निरपेक्ष देशों और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र एवं यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व के देश दो पृथक प्राथमिकताओं के आधार पर दो समूहों में बंट गए। **एक समूह विकासशील देशों का था जिसे निरपेक्ष रहते हुए अपने समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करना था जबकि दूसरा समूह उन विकसित राष्ट्रों का था जो विकास में सहयोग के नाम पर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे।** विकास के विस्तार में एक सहायक उपकरण के रूप में संचार माध्यमों की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए विकासशील देशों ने इस ओर ध्यान दिया। तकनीकी विकास के साथ संचार माध्यमों की प्रभाव क्षमता का भी विस्तार हुआ। एक साथ करोड़ों लोगों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण संचार की मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाने लगा। इस विस्तारीकरण में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तृतीय विश्व की ग्रामीण आबादी तक आसान पहुंच के कारण रेडियो एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में विश्व में प्रचलित हुआ। इसी प्रकार शहरों में टेलीविजन के प्रसारण एवं प्रभाव क्षमता का तेजी से विस्तार हुआ और तीसरी दुनिया जिसमें भारत भी शामिल था, के लोगों ने इसे विकास के एक माध्यम के रूप में स्वीकार किया।

संचार माध्यम विकास में कई प्रकार से योगदान करते हैं। वे वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, नई जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं तथा व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। भारत में 70 के दशक में **साइट** (Satelite Instructional Television Experiment) का प्रयोग इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार द्वारा संचार माध्यमों के इस बहुआयामी उपयोग के सार्थक परिणामों से प्रेरित होकर अनेक देशों ने शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में इसका सफल प्रयोग किया। विकास की गति को बढ़ाने में संचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। **संचार माध्यमों की विकासात्मक उपयोगिता और महत्व ने भी विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य दूरी बढ़ाई है। विकसित देशों ने संचार माध्यमों के द्वारा अपनी संस्कृति, व्यापार, शिक्षा आदि का प्रचार–प्रसार आरम्भ किया जबकि विकासशील देशों की प्राथमिकताएं भिन्न थीं। विकासशील देशों में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याएं विकराल रूप में सामने थीं और संचार साधनों का उपयोग इस हेतु किया जाना आवश्यक था।** विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य वैचारिक मतभेद कम करने में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों विशेषकर संयुक्त राष्ट्र ने सराहनीय भूमिका अदा की।

संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र 59–1, में स्वतन्त्र सूचना प्रवाह के बारे में स्पष्ट किया गया कि –

"All states should proclaim politics under which the free flow of information within countries and across frontiers will be protected. The right to seek and transmit information should be insured in order to enable the public to ascertain facts and appraise events."

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सूचना की स्वतन्त्रता के प्रयासों में निरन्तरता लानी शुरू की। उसने अन्तरिक्ष के स्वतन्त्र एवं समान उपयोग के प्रयास शुरू किए। 1959 में बाह्य अन्तरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग की समिति (Committee on peaceful uses of outer space, COPUOS) बनी। इसके आधार पर 1967 में हुए समझौते

के प्रथम अनुच्छेद में इसे The province of all manbind घोषित किया गया, ताकि इसका उपयोग सम्पूर्ण मानवता के लिए किया जा सके। किन्तु विकासशील देश इस आशंका से ग्रस्त थे कि विकसित राष्ट्र Direct Broadcast Satellite-DBS का उपयोग उनकी सामाजिक और राजनीतिक विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए करेंगे।

1976 में नैरोबी में यूनेस्को के अधिवेशन में सूचना एवं संचार जगत की विसंगतियों को दूर करने के लिए सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया। इसे **मैकब्राइड कमीशन** के नाम से जाना जाता है। आयोग में विश्व के चुने हुए संचार विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, पत्रकारिता एवं प्रसारण के विशेषज्ञ आदि शामिल थे। कनाडा के विश्वविख्यात संचारविद् मार्शल मैकलूहन भी इस आयोग के सदस्यों में शामिल थे। मैकब्राइड ने चार प्रश्न उठाए –

1- What is meant by free and balance flow of information ?

2- What does a 'New World Information Order' mean and what is its inter-relationship with the new international economic order ?

3- How may the 'Right to communicate' with all its ethical and legal implications. He achieved as a new line of thought and action in the whole communication field ?

4- How can the objectivity and independence of the media be assured and protected ?

1978 में यूनेस्को के पेरिस अधिवेशन में भी इस विषय पर महत्वपूर्ण बहस हुई। इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि संचार माध्यमों की भूमिका के सम्बन्ध में एक घोषणापत्र तैयार हुआ। मैकब्राइड कमीशन ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। **Many Voices, One World** शीर्षक से प्रस्तुत इस रिपोर्ट में संचार के गुणात्मक सुधार हेतु 82 संस्तुतियां दी गईं। **रिपोर्ट में संचार माध्यमों के विकास, प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता के क्षेत्र में संचार माध्यमों की उपयोगिता एवं विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में जन माध्यमों की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।**

यूनेस्को के विशेष प्रयासों से 1980 के अधिवेशन में नयी विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था **(NWICO – New world information and communication order)** की स्थापना करने उद्देश्य एवं दिशा निर्देश निर्धारित कर दिये गए। इस व्यवस्था का उद्देश्य तत्कालीन संचार व्यवस्था में व्याप्त असंतुलन को दूर करना था, ताकि सूचना के प्रवाह में विकसित एवं विकासशील देशों के बीच पक्षपातपूर्ण एवं असंतुलित प्रवाह को रोका जा सके एवं एक निष्पक्ष सूचना प्रवाह निर्मित किया जा सके।

इसी दौरान नई दिल्ली, भारत में सम्पन्न हुई गुट निरपेक्ष देशों की बैठक में **गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के न्यूज पूल** के गठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस पूल के अन्तर्गत गूटनिरपेक्ष राष्ट्रों की समाचार एजेन्सियों के बीच समाचारों के आदान–प्रदान की व्यवस्था है, जो समाचारों की प्राप्ति के सन्दर्भ में लम्बे समय तक असन्तुलन एवं पक्षपात का शिकार रहे हैं। इस पूल का काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। आज भी यह पूल कार्यरत है और चार महाद्वीपों एशिया, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका तक इसका कार्यक्षेत्र फैला है। पूल के द्वारा चार भाषाओं में अंग्रजी, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अरबी समाचार प्रेषित किये जाते हैं।

लेकिन उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद वर्तमान विश्व में पाश्चात्य मीडिया विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन एवं उसके मित्र देशों की समाचार एजेन्सियों एवं संस्थानों का वर्चस्व सर्वाधिक है। इसका ज्वलन्त उदाहरण अफगानिस्तान युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, ईराक युद्ध, वर्तमान सीरिया के गृहयुद्ध, अफ्रीका के अनेक देशों में छिड़े गृहयुद्धों के साथ इजराइल एवं फिलिस्तीन मुद्दे तथा कोरिया के मुद्दे में प्रसारित सूचनाएं हैं। इन भ्रामक सूचनाओं के प्रतिकार स्वरूप जब तक क्षेत्रीय मीडिया ने वास्तविक तस्वीर दिखानी शुरू की तो उनके कर्मियों एवं दफ्तरों पर हमला किया गया। **अफगानिस्तान एवं खाड़ी युद्धों के मामले में तो अलजजीरा ने यथार्थ तस्वीर पेश कर पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेण्डों की पोल खोल कर रख दी।** अघोषित अमेरिकी सेंसरशिप के चलते वही सूचनाएं प्रसारित की जा रही थीं जो उनके शासन की नीतियों की समर्थक थीं। इसके विपरीत वास्तविक सूचनाएं प्रसारित करने वाले पत्रकारों को, फिर वे चाहे किसी भी देश के हों, को सेंसर एवं शस्त्र बल से दबाने का पुरजोर प्रयास किया गया। **इसके अलावा विकासशील एवं तीसरी दुनिया के देशों में विकास की योजनाओं के लिए किए जाने वाले कार्यों के विषय में भी ये पश्चिमी एजेन्सियां प्रोपेगेण्डा फैलाती हैं, इनका मूल उद्देश्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य पश्चिमी देशों का हित होता है।**

इसका हालिया उदाहरण विश्व पर्यावरण के सम्बन्ध में चीन तथा भारत के ऊपर कार्बन उत्सर्जन का दोष मढ़ना, अमेरिका एवं पश्चिम के देशों में खाद्य संकट के लिए भारत के लोगों द्वारा अधिक भोजन किया जाना, जैसी बातें फैलायी गईं। इसके अलावा पश्चिमी उत्पादों को श्रेष्ठ बताने का प्रचार लगातार दशकों से होता आ रहा है, ताकि भारत, ब्राजील एवं चीन जैसे वृहद मध्यमवर्गीय देशों के बाजारों में इनके सामानों की खपत बढ़ती रहे और वे मुनाफे का धंधा करते रहें। ये सब घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सूचनाओं के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे जहां एक ओर सूचनाओं, समाचारों का स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रवाह बाधित होता है, वहीं सूचना प्राप्त करने के वैयक्तिक अधिकारों का हनन भी होता है। अतः इस सम्बन्ध में किए गए अब तक के सभी प्रयास इस दिशा में उठाया गया पहला कदम प्रतीत होता है। मंजिल तक पहुंचने के सार्थक प्रयास किए जाने आवश्यक हैं जिससे विकसित देशों द्वारा जनमाध्यमों के दुरूपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।

BRICSICO – BRICS information and communication order की स्थापना इस दिशा में उठाया गया एक गंभीर एवं सार्थक कदम हो सकता है। गोल्डमैन सैस के जिम ओ'नेल ने 2001 में प्रकाशित **'बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स'** (यानि ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा बेहतर वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण), शीर्षक आलेख में अनुमान व्यक्त किया था कि रूस के अद्भुत समावेश के साथ ब्राजील, भारत एवं चीन के रूप में प्रमुख दक्षिणी आर्थिक शक्तियों का आरोहण होगा। इनका विश्व के सामूहिक एवं व्यक्तिगत आर्थिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा और अगले पचास वर्षों में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होंगी। यूएनडीपी की वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट **'द राइज आफ द साउथ : ह्यूमन प्रोग्रेस इन ए डाइवर्स वर्ड'** में कहा गया है कि "150 वर्षों में पहली बार विश्व की तीन प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं– ब्राजील, चीन एवं भारत का संयुक्त उत्पादन उत्तर की पुरानी औद्योगिक शक्तियों– कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एवं अमेरिका के जीडीपी के समान है।"

लेकिन मानव विकास रिपोर्ट के अन्य मानकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग समानता, शिशु मृत्युदर, जीवन प्रत्याशा, आय के मानडण्ड आदि पर भारत सहित इन देशों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। भारत गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ–साथ स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा आदि मोर्चों पर लगातार लड़ाई लड़ रहा है। चीन एवं ब्राजील की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही है। सोवियत संघ की टूट के बाद हर मोर्चे पर बिखर चुके रूस के पुनः एक महाशक्ति के रूप में उभरने से अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में भय का माहौल है। अनेक विशेषज्ञ इसे शीत युद्ध की वापसी की संज्ञा दे रहे हैं, तो अनेक एकध्रुवीय विश्व के पुनः द्विध्रुवीय हो जाने से वैश्विक सन्तुलन की बात कर रहे हैं। **ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि ब्रिक्स देशों के मध्य सूचना प्रवाह के एक ऐसे पूल की स्थापना हो, जो इन देशों के आन्तरिक एवं परस्पर विकास के मार्ग में आ रही बाधाओं से लड़ाई में उत्तरदायी, समावेशी एवं सामूहिक समाधान तैयार करने में इन देशों की मदद करे साथ ही साथ वैश्विक सूचना प्रवाह में विकसित देशों द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेण्डा का मुकाबला भी कर सके।**

इस दिशा में ब्रिक्स देशों ने कदम भी बढ़ा दिया है। मास्को में वर्ष 2015 में आयोजित ब्रिक्स देशों के संचार मंत्रियों के सम्मेलन में विश्व सूचना तकनीकि उद्योग के एकाधिकार को खत्म करने और इस दिशा में पारस्परिक सहयोग से जुड़े सवालों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ इण्टरनेट के बुनियादी ढांचे के अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंधन के लिए एक तन्त्र के विकास पर भी चर्चा हुई। सम्मेलन में 5–जी टेक्नॉलाजी, क्लाउड सर्विसेज एवं इण्टरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। चीनी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने बताया कि **2014 तक ब्रिक्स देशों में इण्टरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 अरब 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानि विश्व के 40 प्रतिशत इण्टरनेट उपयोगकर्ता ब्रिक्स के पांच देशों में रहते हैं।** किन्तु इसके बावजूद ब्रिक्स देशों में पारस्परिक सम्पर्क का स्तर एवं इण्टरनेट का बुनियादी ढ़ांचा विकसित देशों के मुकाबले काफी कमजोर एवं पिछड़ा हुआ है। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रमुख मीडिया संगठनों ने वैश्विक सूचना परितन्त्र बनाने और अधिक उचित अन्तर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

नयी वैश्विक संचार व्यवस्था के फेल हो जाने और अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाने की स्थिति में वैश्विक सूचना संतुलन हेतु विश्व की 43 प्रतिशत आबादी, 37 प्रतिशत जीडीपी एवं विश्व व्यापार में 17 प्रतिशत

हिस्सेदारी वाले ब्रिक्स देशों के लिए एक ऐसी सूचना एवं संचार व्यवस्था **BRICSICO** की आवश्यकता है जिसके द्वारा –

1 – ब्रिक्स देशों के मध्य एक निष्पक्ष सूचना एवं संचार प्रणाली की स्थापना की जा सके।

2 – ब्रिक्स देशों के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक देश के आन्तरिक सूचना तन्त्र को मजबूती प्रदान की जा सके। ताकि पश्चिमी समाचार एजेन्सियों पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके।

3 – ब्रिक्स देशों में हो रहे विकास कार्यों को समुचित समर्थन दिया जा सके।

4 – सूचना तकनीकी के क्षेत्र में साफ्टवेयर एवं उपकरणों के मामले में ब्रिक्स देशों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किये जाएं।

5 – सूचनाओं के स्वतन्त्रता एवं विस्तारीकरण के मार्ग में आने वाली आन्तरिक एवं बाह्य बाधाओं को दूर करते हुए वर्तमान वैश्विक सूचना प्रवाह को संतुलित किया जाए।

6 – एकाधिकारी, सार्वजनिक, निजी एवं अतिकेन्द्रीकृत व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त किया जाए।

7 – सूचना के साधनों एवं माध्यमों की संख्या में वृद्धि करना तथा सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सुनिश्चित किया जाए।

8 – पत्रकारों एवं जनमाध्यमों से जुड़े लोगों की उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित हो।

9 – ब्रिक्स देशों के अलावा अन्य विकासशील देशों को उनकी क्षमता के अनुसार उपकरण, प्रशिक्षण आदि में वृद्धि करना तथा इन देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप संचार व्यवस्था का विकास किया जा सके।

10 – विकसित राष्ट्रों में सहयोग की भावना जागृत की जा सके।

11 – सूचना के अन्तर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान में वैयक्तिक अधिकारों तथा सहभागिता का सम्मान किया जाए।

12 – प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्य रखते हुए सूचना तन्त्र का विकास करना।

वर्तमान में ब्रिक्स देशों में शामिल भारत और ब्राजील जहां तीसरी दुनिया के देश से निकलकर विकासशील देशों की श्रेणी में खड़े हैं, चीन और दक्षिण अफ्रीका विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं वहीं रूस विकसित देशों की कतार में खड़ा है। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देशों द्वारा एक ऐसी समाचार व्यवस्था निर्मित की जाएगी, जो न केवल वैश्विक सूचना संतुलन स्थापित करेगी वरन वैश्विक शांति एवं विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

सन्दर्भ –

1. संजीव भनावत, जनसंचार के सिद्धान्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2012
2. साइट (Satelite Instructional Television Experiment) , 1975
3. संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र 59–1
4. Committee on peaceful uses of outer space, COPUO, 1959
5. Many Voices, One World, मैकब्राइड कमीशन, यूनेस्को, 1976 तथा 1978
6. NWICO – New world information and communication order, 1980
7. गोल्डमैन सैस के जिम ओ'नेल का 2001 में प्रकाशित 'बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स' (यानि ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा बेहतर वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण), शीर्षक आलेख।
8. यूएनडीपी की वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट 'द राइज आफ द साउथ : ह्यूमन प्रोग्रेस इन ए डाइवर्स वर्ल्ड'।

डॉ. सुमीत द्विवेदी
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ.प्र.।